भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3697
जिसका उत्तर मंगलवार 09 अगस्त, 2016 को दिया जाना है

ऑटो घटकों के निर्यात में कमी

3697. श्रीमती रक्षाताई खाडसे:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात विशेषकर ऑटो के घटकों/कलपुर्जों जिसमें पहली बार लगभग 3.7 प्रतिशत की गिरावट है, का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऑटो कलपुर्जों के निर्यात में आई गिरावट को रोकने तथा भारत को विश्व में ऑटो घटकों/कलपुर्जों का हब बनाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): अप्रैल-जून, 2015 के दौरान 1056.33 मिलियन अमेरीकी डॉलर के ऑटो कलपुर्जा निर्यात की तुलना में, अप्रैल-जून, 2016 के दौरान, 3.82% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए, ऑटो कलपुर्जा का निर्यात 1016 मिलियन अमेरीकी डॉलर का रहा।

(ख): भारत के सबसे बड़े निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में निर्यात में तीव्र गिरावट देखी गई थी। ऑटो कलपुर्जों के निर्यात में गिरावट का प्रमुख कारण प्रमुख बाजारों में मांग में कमी आना है। यह सेक्टर आयातित कच्चे माल की कीमत में वृद्धि से भी प्रभावित हुआ है।

(ग) और (घ): भारत, ऑटो पार्टस के वैश्विक हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देना एक अनवरत प्रक्रिया है; ऑटो सेक्टर के विकास हेतु किए गए कुछ विशिष्ट उपाय नीचे दिए गए हैं:-

i) ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2016-26 (एएमपी 2026) में विकास हेतु भारत में पारि-तंत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

ii) विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत मर्चेण्डाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम(एमईआईएस) के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन दिए गए हैं।

iii) सरकार ने ऑटो कलपुर्जा सेक्टर के लिए प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर 3% ब्याज समकारी योजना की अनुमति दे दी है।

iv) वाणिज्य विभाग द्वारा बाजार विकास सहायता(एमडीए) और बाजार आकलन पहल(एमएआई) स्कीमों के माध्यम से लगातार सहायता।

v) अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के बाजारों में प्रवेश पाने हेतु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए जा रहे हैं।

*****